

महात्मा गांधी नरेगा का सुशासन संकेतक फ्रेमवर्क का प्रसार और सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना 28 वें - 29 नवंबर 2017

अच्छी प्रशासन पहल Good Governance Initiatives



7 रजिस्टर्स 7 Registers

मनरेगा के विवरण रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टर्स का एक अनिवार्य सेट एक में काम करता है सरल, आसान और प्रभावी तरीका।

इससे पहले, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में औसतन 22 रजिस्टर्स का उपयोग किया जा रहा था।

मंत्रालय ने रजिस्टर्स की संख्या को सरल और कम किया।

ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए रखा गया ताकि ग्राम रोजगार सहायक को अपना समय प्रभावी ढंग से और लाभप्रद रूप से बिताने में सक्षम बनाया जा सके।

बनाए रखने के निर्देशों के साथ इन 7 रजिस्टर्स के प्रारूप उनमें से प्रत्येक को एक पुस्तिका में संकलित किया गया है और अक्टूबर 2016 में राज्य के साथ साझा किया गया है।

रूपरेखा तैयार करना Laying out of Frameworks

S. No.	Initiative	Date of Consultation with States/UTs	Date of Issuing of Framework
1	7 Registers	8 th March 2016	3 rd October 2016
2	Citizen Information Board	8 th February 2017	7 th April 2017
3	Case Records/ Work Files	5 th June 2017	19 th July 2017
4	Job Cards	10 th February 2017	28 th August 2017

क्षेत्र का दौरा Field Visits

8 States covered:

- आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh
- छत्तीसगढ़ Chhattisgarh
- हरियाणा Haryana
- झारखंड Jharkhand
- कर्नाटक Karnataka
- ओडिशा Odisha
- पंजाब Punjab
- राजस्थान Rajasthan



6 States planned:

- असम Assam
- गुजरात Gujarat
- मध्य प्रदेश Madhya Pradesh
- सिक्किम Sikkim
- तमिलनाडु Tamil Nadu
- उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh

फील्ड विजिट से अवलोकन 7 रजिस्टर्स Observations from the Field Visits 7 Registers

महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखों का विवरण, रख-रखाव जानकारी का रिकॉर्ड राज्यों के साथ साझा निर्देश / प्रारूप।

संतोषजनक

छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा

संतोषजनक नहीं है

राजस्थान, पंजाब, हरियाणा



जॉब कार्ड Job Card

परिवारों को जारी एंटाइटलमेंट कार्ड कार्यक्रम के तत्वों की महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्डिंग टूल हर समय लाभार्थी के कब्जे में होना चाहिए।

जॉब कार्ड सत्यापन

जॉब कार्ड की संशोधित जानकारी अपडेट जारी किए गए जॉब कार्ड की समीक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास

जॉब कार्ड डिजाइन

संकेतक फ्रेमवर्क साझा किया

डिजाइन सभी राज्यों में एक-समान होगा।

केस रिकॉर्ड्स वर्क फाइल Case Records/ Work File

MGNREGA के तहत एक काम से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों का एकीकरण

भौतिक फाइल

संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड केस रिकॉर्ड / वर्क फाइल में भरे हुए हैं

क्रमिक तरीके से।

यह परियोजना के कार्य के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और लेखा परीक्षा करने में सक्षम बनाता है

कार्यान्वयन चरण और इसके पूरा होने के बाद भी।

देश भर में कुछ समानता लाने के लिए, एक संकेतक ढांचा तैयार किया गया था और गोद लेने के लिए राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया।

कार्य फाइल में शामिल किए जाने वाले सभी आवश्यक विवरणों के विवरण के साथ एक चेकलिस्ट रही है

नागरिक सूचना बोर्ड Citizen Information Board

काम शुरू होने पर हर मनरेगा कार्य स्थल पर रखा गया।

जमीनी स्तर पर जानकारी का मूल स्रोत।

कार्यक्रम के बारे में दृश्यता, पारदर्शिता और जागरूकता बढ़ाने के लिए माध्यम।

डिजाइन, सामग्री, लेआउट में पहले व्यापक रूप से गिबन गिबनता प्रचलित थी।

बनाए गए अन्य मुद्दों में मायब प्रोग्राम लोगो, अनुचित प्लेसमेंट, आयाम और रंग में गिबनता।

टिन, पलेक्स शीट इत्यादि सहित सामग्री स्थानित्व के बारे में चिंता उठाती है।

समानता लाने और संबंधित करने के लिए राज्यों के साथ साझा फ्रेमवर्क साझा किया गया

Observations from the Field Visits Job Cards

क्षेत्र भ्रमण से जॉब कार्ड का निरीक्षण

जॉब कार्ड सत्यापन नौकरी कार्ड में पंजीकृत जानकारी की पुष्टि और अद्यतन करने की प्रक्रिया।

संतोषजनक...छत्तीसगढ़

संतोषजनक नहीं है...राजस्थान, पंजाब, हरियाणा

जॉब कार्ड डिजाइन और प्रारूप राज्य भर में बर्बाद और मानकीकृत होगा।

राज्यों के साथ साझा किए गए इंडिकेटिव फ्रेमवर्क।

संतोषजनक...छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड

संतोषजनक नहीं है...पंजाब, हरियाणा, ओडिशा

Observations from the Field Visits Case Records/ Work File

क्षेत्र भ्रमण केस रिकॉर्ड्स / वर्क फाइल से अवलोकन

महात्मा गांधी नरेगा के काम से संबंधित सभी दस्तावेजों का एकीकरण

संकेतक फ्रेमवर्क राज्यों के साथ साझा किया।

संतोषजनक

कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा

संतोषजनक नहीं है

हरियाणा, राजस्थान, पंजाब



Observations from the Field Visits Citizen Information Boards

क्षेत्र के निरीक्षण नागरिक सूचना बोर्डों का मूल्यांकन

अधिनियम में उल्लिखित नागरिक सूचना प्रणाली का आवश्यक उपकरण राज्यों के साथ साझा सूचक फ्रेमवर्क।

संतोषजनक

छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब (डिपेंडेंट पब्लिश)

संतोषजनक नहीं है

झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान



Way Forward

आगे का रास्ता

प्रशिक्षण कैंपेस

क्षेत्र कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण

कार्यशालाएं

संपर्क / विनिमय कार्यक्रम (जिला स्तर)